RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

INDORE ■ 21 OCTOBER TO 27 OCTOBER 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 9 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

भारत में सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए ज़नरूफ सस्टेनेबल, रिलाएबल और अफोर्डेबल एनर्जी

Page 2

शक्ति पम्प्स के घरेलू व्यापार में 178 फीसदी वृद्धि, निर्यात में 33 फीसदी इज़ाफा

Page 3

लक्जरी ऑल-राउंडर ऑडी क्यू2 भारत में

Page 7

editoria!

ताकि मांग बढ़े

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जिन सुविधाओं की घोषणा की, वह लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था में नया जोश भरने की एक और कवायद है। ये व्यावहारिक कदम हैं, और इनसे अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग के बढ़ने की उम्मीद बांधी जा सकती है। इन सुविधाओं के तहत तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को दस हजार रुपये की करमुक्त राशि अग्रिम भुगतान के रूप में दी जाएगी और कर्मचारी इसे 31 मार्च तक किसी भी त्योहार में खर्च कर सकेंगे। उन्हें दस किस्तों में इसे लौटाने की सुविधा होगी। इसी तरह, 'एलटीसी कैश वाउचर स्कीम' में कर्मचारी 'रिइंबर्समेंट' की बजाय सीधे नकदी का दावा कर सकेंगे और इस राशि का इस्तेमाल भी उन्हें 31 मार्च से पूर्व कर लेना होगा। अपने कर्मचारियों के अलावा केंद्र ने राज्यों को भी पूंजीगत व्यय के लिए 12,000 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त कर्ज देने का एलान किया है। राज्य 31 मार्च तक अपनी नई-पुरानी योजनाओं पर इसे खर्च कर सकेंगे और उनके पास अगले 50 वर्षों में इसे चुकाने की सहूलियत होगी। सरकार का आकलन है, जो तर्कसंगत भी है कि इन कदमों से बड़ी मांग पैदा होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम देशी-विदेशी वित्तीय व रेटिंग संस्थाओं के जो आकलन हैं, वे सरकार की पेशानी पर बल डालने के लिए काफी हैं। हालांकि, अनलॉक की प्रक्रिया के आगे बढ़ने के बाद बाजार में स्थितियां कुछ सुधरी हैं, खुद वित्त मंत्री ने भी आपूर्ति श्रृंखला में सुधार की स्थिति पर संतोष जताया है। लेकिन यह एक सर्वमान्य बात है कि बाजार में मांग बढ़ाए बिना अर्थव्यवस्था की पटरी पर वापसी मुमकिन नहीं है। और मांग बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि उपभोक्ताओं के जेहन से महामारी से जुड़ी आशंकाएं तिरोहित हों और वे खुलकर खर्च करने की स्थिति में आएं। लॉकडाउन ने मध्यवर्ग को किफायती खर्च के लिए बाध्य किया है और जब तक कोविड-19 से जुड़ी स्थितियां सामान्य के करीब नहीं पहुंचेंगी, सामाजिकता नहीं बढ़ेगी, तब तक उनका पूर्व स्थिति में लौटना कठिन है। ऐसे में, केंद्रीय कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं की अहमियत समझी जा सकती है। दुनिया भर के कई अर्थशास्त्री और विपक्ष के नेता केंद्र सरकार से अपील करते रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए उसे गरीबों की जेब में कुछ अरसे तक पैसे डालने पड़ेंगे, ताकि बाजार में मांग की स्थिति सुधरे। उनका जोर खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऊर्जा पैदा करने पर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा देने की इसकी क्षमता असंदिग्ध है। कोरोना-काल ने तो इसके प्रामाणिक आधार भी मुहैया कराए हैं। जब सभी क्षेत्रों की विकास दर जमीन पर लेट रही थी, तब कृषि क्षेत्र देश को उम्मीद की रोशनी दिखा रहा था। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ठोस क्षमताओं को देखते हुए ही मनरेगा का बजटीय आबंटन बढ़ाया है। भारत में त्योहार अर्थव्यवस्था को मजबूत संबल देते हैं। यही वक्त होता है, जब खासतौर से ग्रामीण लोग दैनिक जरूरतों के आगे की खरीदारी करते हैं। विशेष रूप से दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, ईद, गुरुपर्व और क्रिसमस हमारी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देते आए हैं। कोरोना ने इस साल के त्योहारों का रंग फीका कर दिया है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के उडे़ रंग इन्हीं की बदौलत सुर्खरू भी होंगे। सरकार को कुछ और राहतें असंगठित क्षेत्रों पर भी बरसानी होंगी।

Loan Moratorium: दिवाली पर सरकार देगी आम आदमी को बड़ा तोहफा!

चुनिंदा लोन पर ब्याज माफ करने के लिए तैयार

नयी दिल्ली। एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, चुनिंदा लोन पर ब्याज माफी को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि, सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार अभी इसकी घोषणा नहीं करेगी, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आपको बता दें कि लोन मोरेटोरियम के जारिए आप अपनी ईएमआई कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब बड़ी संख्या में लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे थे तो रिजर्व बैंक की तरफ से लोन मोरेटोरियम की पेशकश की गई थी। लोगों ने मार्च से अगस्त तक मोरेटोरियम योजना यानी किश्त टालने के लिए मिली छूट का लाभ लिया था। लेकिन उनकी शिकायत थी कि बैंक बकाया राशि पर अतिरिक्त ब्याज यानी ब्याज के ऊपर ब्याज लगा रहे हैं। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

अब क्या हुआ?

सूत्रों ने बताया कि सीसीईए की बैठक में आज लोन पर ब्याज माफी को मंजूरी मिल गई है, लेकिन बैठक में चुनिंदा लोन पर ही ब्याज माफी को मंजूरी मिली है। इसका फायदा 2 करोड़ रुपये तक के लोन लेने वालों को मिलेगा। प्रस्ताव के मुताबिक चुनिंदा लोन के लिए ब्याज

पर ब्याज माफ किया जायेगा। सरकार ब्याज पर ब्याज का करेगी। 2 करोड़ रु तक के लोन की EMI के ब्याज पर ब्याज माफ करने का प्रस्ताव है। केंद्र को 2 नवंबर तक स्कीम पर सर्कुलर जारी करने का निर्देश - 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार को ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। इसके लिए केंद्र को एक महीने का वक्त क्यों चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि अगर सरकार इस पर फैसला ले लेगी तो हम तुरंत आदेश पारित कर देंगे। इस पर सॉलीसीटर जनरल ने कहा कि सभी लोन अलग-अलग तरीके से दिए गए हैं। इसलिए सभी से अलग-अलग तरीके से निपटना होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को लेकर 2 नवंबर तक सर्कुलर लाया जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार 2 नवंबर तक ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को लेकर सर्कुलर जारी कर देगी।

क्या है पूरा मामला- कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था। उस समय उद्योग धंधे पूरी तरह बंद थे। इसीलिए कारोबारियों और कंपनियों के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो गई। कई लोगों की नौकरियां चली गईं। ऐसे में लोन की किस्तें चुकाना मुश्किल था। ऐसे में रिजर्व बैंक ने लोन मोरेटोरियम की सहूलियत दी थी। यानी लोन पर किस्तें टाल दी गई थीं। किसी लोन पर मोरेटोरियम का लाभ लेते हुए किस्त नहीं चुकाई तो उस अवधि का ब्याज मूलधन में जुड़ जाएगा। यानी अब मूलधन + ब्याज पर ब्याज लगेगा। इसी ब्याज पर ब्याज का मसला सुप्रीम कोर्ट में है।

सरकार 30.67 लाख कर्मचारियों को देगी 3,737 करोड़ रुपये का बोनस

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने बुधवार को 30.67 लाख गैर-राजपत्रित केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया। कुल 3,737 करोड़ रुपये बोनस मिलने से कर्मचारी त्योहारों के दौरान खर्च के लिये प्रोत्साहित होंगे और इससे कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में 2019-20 के लिये उत्पादकता और गैर-उत्पादकता से संबद्ध बोनस देने का फैसला किया गया। बैठक में किये गये फैसले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि त्योहारों से पहले केंद्र सरकार के 30 लाख गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को 3,737 करोड़ के बोनस का भुगतान किया जाएगा। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और त्योहारों के समय मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा होगा।'' कर्मचारियों को बोनस एक सप्ताह के भीतर दिया जाएगा। आधिकारिक बयान में कहा गया है, ''गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को पिछले साल के उनके प्रदर्शन के आधार पर बोनस दुर्गा पूजा/दशहरा से पहले दिया जाता है।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

कमजोर मांग से कच्चातेल वायदा कीमतों में गिरावट

नयी दिल्ली। एजेंसी

कमजोर हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को कम किया जिससे वायदा बाजार में कच्चा तेल बुधवार को 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,035 रुपये प्रति बैरल रह गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में नवंबर महीने की डिलिवरी वाले कच्चा तेल अनुबंध की कीमत 10 रुपये यानी 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,035 रुपये प्रति बैरल रह गयी। इसमें 2,800 लॉट के लिये कारोबार हुआ। हालांकि, कच्चातेल के दिसंबर माह में डिलिवरी वाले अनुबंध की कीमत 34 रुपये यानी 1.11 प्रतिशत की तेजी के साथ 3,084 रुपये प्रति बैरल हो गयी। इसमें 24 लॉट के लिये कारोबार हुआ। वैश्विक स्तर पर, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड का भाव 1.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 41.18 डॉलर प्रति बैरल चल रहा था और ब्रेंट क्रूड का भाव 1.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 42.58 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर था।

भारत में सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए ज़नरूफ सस्टेनेबल, रिलाएबल और अफोर्डेबल एनर्जी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत उन देशों में से एक है जिसने रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा प्रोडक्शन पूरा किया है। यह पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के रूप में अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार, 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन क्षमता का 40 प्रतिशत स्थापित करने के अपने लक्ष्य पर तेजी से प्रगति कर रहा है। यह रिन्यूएबल एनर्जी को भारत के इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान के प्रमुख पहलुओं में से एक बनाता है। इतना ही नहीं ऊर्जा के स्वच्छ, रिलाएबल और अफोर्डेबल सोर्स तक पहुंचने के लिए लोगों ने बहुत ही दिलचस्पी दिखाई है, जो शायद पिछले कुछ वर्षों में सोलर पैनलों के तेजी से फैलने का कारण भी है।

शहरी मार्केट्स पर अपनी पकड़ बनाने और मप्र, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के बाद, भारत की प्रमुख होम टेक कंपनी सरकार की सहायता के लिए अग्रेसिवली काम कर रही है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और उन्हें सोलर प्रोडक्ट्स की अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी के बारे में जागरूक किया जा सके। ज़नरूफ, ज़नसोलर के अंतर्गत कई सोलर प्रोडक्ट्स को सामने लाया है, जिसमें सोलर पैनल, बैटरी, चेज कंट्रोलर, इनवर्टर और बहुत कम दरों के कई किफायती सोलर कॉम्बो शामिल हैं। कंपनी का मुख्य उद्देश्य देश के उन क्षेत्रों में सोलर एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन पेश करके बिजली के एक विश्वसनीय स्रोत तक पहुंच प्रदान करना है, जहां बिजली की पहुंच नहीं है। भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन सोलर एनर्जी को प्रमुखता देने का एक और महत्वपूर्ण कारण है। 300 दिनों तक सूरज की रोशनी और साफ़ आसमान के साथ दिन-प्रतिदिन के उपयोग के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग करने का कार्य उचित प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के साथ मुश्किल नहीं है।

सोलर एनर्जी के उपयोग पर अपनी बात रखते हुए, ज़नरूफ के संस्थापक और सीईओ, श्री प्राणेश चौधरी कहते हैं कि, 'भारत में अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बिजली की सप्लाई खराब और अप्रत्याशित है। हमारा लक्ष्य देश के हर नुक्कड़ तक बिजली की प्रॉपर सप्लाई करना है।' सोलर समाधानों की अफोर्डेबिलिटी को व्यक्त करते हुए वे आगे कहते हैं कि, 'सोलर पर स्विच करना एक बार के इन्वेस्टमेंट की तरह है और इसलिए यह बहुत ही कॉस्ट-इफेक्टिव है। कारों या बाइक की तरह आपको कुछ दिनों के अंतराल में सोलर सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं करना होगा। इसके साथ ही, आपकी छतों पर पैनल स्थापित करने से बैटरी में दिन के दौरान जो सोलर एनर्जी का स्टोर होता है आप उसे पूरे दिन तक इस्तेमाल कर सकते है। 'सोलर सिस्टम तेज़ी से पावर का एक लोकप्रिय स्रोत बन रही है, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, यह भारत में सबसे तेजी से बढ़ती रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र है और वह भी कम से कम खर्चों पर।

केयर्न आयल एण्ड गैस ने प्रचुर शाह को डिप्टी सीईओ नियुक्त किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

तेल एवं गैस उत्पादन करने वाली कंपनी केयर्न आयल एण्ड गैस ने मंगलवार को प्रचुर शाह को कंपनी का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (डिप्टी सीईओ) नियुक्त करने की घोषणा की। केयर्न आयल एण्ड गैस, वेदांता समूह की कंपनी है। कंपनी ने जारी एक वक्तव्य में इसकी जानकारी देते हुये कहा कि इससे पहले प्रचुर शाह कंपनी में नये उद्यम निदेशक की भूमिका निभाते रहे हैं। इस भूमिका में रहते हुये उन्होंने खुला क्षेत्र लाइसेंसिग नीति के तहत कंपनी की विस्तार योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। प्रचुर को ऊर्जा क्षेत्र में दो दशक से भी अधिक का अनुभव है और वह 2018 में केयर्न आयल एण्ड गैस में आये। वह इससे पहले स्लमबर्गर में -भारत और बांग्लादेश- क्षेत्र के प्रबंध निदेशक थे। प्रचुर आईआईटी बंबई के छात्र रह हैं और उन्होंने दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया और लेटिन अमेरिका सहित कई देशों में काम किया है जिससे उन्हें तेल एवं गैस कारोबार की गहरी समझ है।

मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया ने भारत में तुमाकुर, कर्नाटक में अपने 28वें मेट्रो होलसेल स्टोर का उद्घाटन किया

आईपीटी नेटवर्क

मेट्रो कैश एंड कैरी, जो भारत का सबसे बड़ा संगठित होलसेलर एवं फूड स्पेशलिस्ट, है, ने तुमाकुर में अपने पहले मेट्रो होलसेल स्टोसर का उद्घाटन किया। यह नई स्टोर, जो भारत में मेट्रो की 28वीं होलसेल स्टोटर है, का उद्घाटन श्री जीएस बासवराज, सांसद, तुमाकुर कंस्टिट्यूएंसी, कर्नाटक और श्री जी।बी। ज्योदति गणेश, विधायक, तुमाकुर, तुमाकुर कंस्टिट्यूएंसी, कर्नाटक और मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया के निदेशक - ऑफर मैनेजमेंट और सप्लाएई चेन एवं ओन ब्रांड्स, मनीष सबनीस द्वारा किया गया। कर्नाटक राज्य सरकार के अधिकारी, स्थानीय गणमान्य व्यक्ति और प्रमुख सप्लायर पार्टनर्स भी इस अवसर पर मौजूद थे। यह नई स्टोर, कर्नाटक राज्यं की सातवीं मेट्रो स्टोर है। 24000 वर्गफीट में फैली, यह स्टोर तुमाकुर के व्यावसायिक केंद्र - मंडीपेठ मेन रोड पर महत्व पूर्ण रूप से स्थित है और यह शहर के 25,000 से अधिक पंजीकृत ग्राहकों की आवश्य कताएं पूरी करेंगी, जैसे-किराना और ट्रेडर्स; होटल्सज, रेस्टॉरेंट्स एवं कैटरर्स सर्विसेज, कंपनीज एवं ऑफिसेज (एण्ध्) और स्वरोजगारी प्रोफेशनल्स। तुमाकुर जिले के अलावा, आसपास के बाजारों - सीरा, गुबी, तिप्तु, कुनिगल, नितुर, मदुगिरि, दबासपेठ, चिक्कसनायकन हल्ली व अन्या के कारोबारी ग्राहक भी इसका लाभ ले सकेंगे।

भारत के प्रति मेट्रो की वचनबद्धता को दोहराते हुए, मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया के निदेशक - ऑफर मैनेजमेंट और सप्लीई चेन एवं ओन ब्रांड्स, मनीष सबनीस ने कहा, ''तुमाकुर स्टोर, हमारे पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, चूंकि इससे कर्नाटक में हमारा आधार मजबूत होगा। कोविड-19 महामारी के बीच और कमजोर आर्थिक भावना के बावजूद, इस स्टोर का उद्घाटन किया गया है। मेट्रो, भारत में अपने स्टोर फॉर्मेट और टिकाऊ विस्तार के अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित है।

डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे मजबूत खुला

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

डॉलर के मुकाबले रुपया बुधवार यानी 21 अक्टूबर 2020 को मजबूती के साथ खुला। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे की कमजोरी के साथ 73।38 रुपये के स्तर पर खुला। वहीं, मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे की कमजोरी के साथ 73।46 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे की कमजोरी के साथ 73।37 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। -शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की मजबूती के साथ 73।34 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। -गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे की कमजोरी के साथ 73।38 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। -बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे की मजबूती के साथ 73।30 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था।

सरकार ने कंपनियों पर खुद की प्राकृतिक गैस, सीबीएम खरीदने पर लगाई रोक

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने गैस विपणन मामले में दी गई आजादी से संबंधित नये अधिसूचित दिशानिर्देशों में प्राकृतिक गैस और कोल बैड मीथेन (सीबीएम) के उत्पादकों को खुद की गैस खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने 15 अक्टूबर को प्राकृतिक गैस विपणन सुधार को अधिसूचित करते हुये गैस उत्पादकों को एक मानक ई- बोली प्रक्रिया के जरिये गैस का बाजार मूल्य खोजने की आजादी दी थी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने गैस क्षेत्र में इन सुधारों को मंजूरी दी थी। इसके बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। इसके तहत गैस उत्पादकों को उनकी सहयोगी इकाइयों सहित किसी को भी गैस बेचने की छूट दी गई थी। अधिसूचित दिशानिर्देशों में यह कहा गया कि गैस उत्पादक और उसके गैस क्षेत्र समूह में शामिल किसी भी सदस्य को गैस के लिये बोली लगाने अथवा खरीदारी करने की अनुमति नहीं होगी। अधिसूचना में कहा गया है, ''उत्पादकों के सहयोगियों को गैस की बिक्री की अनुमति होगी बशर्ते कि उत्पादक की सहयोगी कंपनी ने खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में भागीदारी की हो।'' हालांकि, गैस क्षेत्र के ठेकेदार और उसके साथ जुड़ी कंपनियों को को बोली प्रक्रिया में भागीदारी के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। इसमें कहा गया है, ''खरीदार और विक्रेता एक ही कंपनी नहीं हो सकती है।'' अधिसूचना में कहा गया है कि ये दिशानिर्देश न केवल परंपरागत प्राकृतिक गैस के मामले में लागू होंगे बल्कि कोल बैड मीथेन (सीबीएम) पर भी नये दिशानिर्देश लागू होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वर्ष 2017 में मध्यप्रदेश स्थित अपने सोहागपुर पूर्वी और सोहागपुर पश्चिम सीबीएम ब्लॉक से निकलने वाली पूरी गैस को खरीद लिया था। कंपनी ने इस गैस का इस्तेमाल महाराष्ट्र स्थित अपने पातालगंगा और नागोथाने पेट्रोरसायन संयंत्र तथा गुजरात के वड़ोदरा एवं जामनगर स्थित संयंत्रों में किया। रिलायंस ने तब सार्वजनिक क्षेत्र की गैस वितरण कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड को बोली में पछाड़ दिया था और सोहागपुर से निकलने वाली गैस को मार्च 2021 तक के लिये हासिल कर लिया था। गेल ने रिलायंस की इस पहल की आलोचना की थी। उसका कहना था कि खुद की गैस खरीदने में रिलायंस को 14 प्रतिशत का कर लाभ मिलेगा क्योंकि एक ही कंपनी समूह के भीतर स्टॉक स्थानांतरण पर वैट लागू नहीं होता है। बाद में सरकार ने इस मामले में रिलायंस से स्पष्टीकरण भी मांगा था। इस तरह की खामियों को दूर करने के लिये ही 15 अक्टूबर की अधिसूचना में यह व्यस्था दी गई है कि इन नये बदलावों के साथ ही बिक्री की प्रक्रिया के संबंध में 11 अप्रैल 2017 की अधिसूचना में सीबीएम ब्लॉक के जल्द मौद्रीकरण को भी संशोधित कर दिया गया है। नये दिशानिर्देशों में गैस उत्पादक क्षेत्र के ठेकेदार को इलेक्ट्रानिक बोलियों के जरिये प्राकृतिक गैस बिक्री की व्यवस्था दी गई है। इसमें पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोलियों के जरिये बाजार मूल्य की खोज की जायेगी। बोली प्रक्रिया एक स्वतंत्र एजेंसी के जरिये चलाई जायेगी। यह स्वतंत्र एजेंसी हाइड्राकोर्बन महानिदेशालय (डीजीएच) के पैनल में शामिल एजेंसियों में से होनी चाहिये।

वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के अंत में

शक्ति पम्प्स के घरेलू व्यापार में 178 फीसदी वृद्धि , निर्यात में 33 फीसदी इज़ाफा

पीथमपुर। आईपीटी नेटवर्क

भारत की ऊर्जा कुशल (एनर्जी एफिशिएंट) पम्प्स तथा सौर ऊर्जा समाधानों के क्षेत्र में अग्रणी, शक्ति पम्प्स इंडिया लिमिटेड, ने 30 सितम्बर 2020 को समाप्त दूसरी तिमाही के अंत तक शानदार वित्तीय प्रदर्शन की उद्घोषणा की। प्रथम तिमाही की तुलना में कम्पनी ने घरेलू व्यापार में 178 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के अंत तक 153 करोड़ रुपये का घरेलू व्यापार किया। यह आंकड़ा इस वर्ष की प्रथम तिमाही की तुलना में 98 करोड़ रुपये अधिक रहा। कंपनी ने इस वर्ष की दूसरी तिमाही के अंत तक 48 करोड़ रुपये का निर्यात किया, जबकि पिछली तिमाही में यह आंकड़ा 36 करोड़ रुपये था।

ग्रामीण, कृषि तथा निर्यात में एनर्जी एफिशिएंट पम्प्स तथा सौर ऊर्जा समाधानों की मांग बढ़ने के कारण कंपनी की निरन्तर उत्कृष्ट प्रदर्शन देने में सफल रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में कंपनी ने 55 करोड़ का घरेलू व्यापार किया था। इस वर्ष की दूसरी तिमाही में निर्यात में 12 करोड़ रुपये की वृद्धि देखी गयी।

इन उत्साहवर्धक परिणामों के बारे में बात करते हुए, श्री दिनेश पाटीदार, चेयरमैन एवम मैनेजिंग डायरेक्टर, शक्ति पम्प्स (इंडिया) लिमिटेड ने कहा- शक्ति पम्प्स के प्रबंधन व टीम के अथक प्रयासों के चलते पिछली तिमाही में हम सोलर पम्पस निर्माण में तो अग्रणी रहे ही, साथ ही कृषि व्यवसाय एवं निर्यात में भी बढौतरी हासिल कर पाये। हमारी विशेषज्ञता, तकनीक, ग्राहकों का भरोसा, राज्य सरकार व केंद्र सरकार की नीतियों और वृद्धि के अवसरों की तलाश से लक्ष्यों तक पहुँचने में आसानी हुई है। हमें विश्वास है कि निर्यात के साथ ही, विभिन्न ग्रामीण और सौर (रिन्यूएबल) ऊर्जा योजनाओं के क्षेत्र में मांग निरन्तर बढ़ेगी। हमने रिसर्च व डेवलपमेंट को हमेशा से महत्व दिया है और आगे भी इस विभाग में निवेश करते रहेंगे।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अप्रैल-अगस्त में 16 प्रतिशत बढ़कर 27.1 अरब डॉलर रहाः सरकारी आंकड़ा

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश में इस साल अप्रैल-अगस्त के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 16 प्रतिशत बढ़कर 27.1 अरब डॉलर रहा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पिछले साल अप्रैल-अगस्त के दौरान देश में 23.35 अरब डॉलर का निवेश आया था। मंत्रालय ने बयान में कहा कि कमाई को फिर से किये गये निवेश को मिलाकर कुल एफडीआई आलोच्य अवधि में 13 प्रतिशत बढ़कर 35.73 अरब डॉलर रहा। बयान के अनुसार, ''किसी वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में यह अबतक का सर्वाधिक एफडीआई है और 2019-20 के पहले पांच महीनों की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2019-20 के पहले पांच महीनों में यह 31.60 अरब डॉलर था।'' कुल एफडीआई प्रवाह 2008 से 2014 में 231.37 अरब डॉलर की तुलना में 2014 से 2020 में 55 प्रतिशत उछलकर 358.29 अरब डॉलर रहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर लिखा है, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिये भारत एक पसंदीदा गंतव्य है।'' उन्होंने कहा कि पिछले छह साल में एफडीआई 55 प्रतिशत बढ़ा। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त के दौरान कोविड-19 संकट के बावजूद एफडीआई प्रवाह 13 प्रतिशत बढ़ा। किसी एक वित्त वर्ष के पहले पांच महीने में यह सर्वाधिक है। मंत्रालय ने कहा, ''एफडीआई आर्थिक वृद्धि को गति देने वाला प्रमुख तत्व है और बिना कर्ज के वित्त का महत्वपूर्ण स्रोत है। सरकार का यह प्रयास रहा है कि एफडीआई नीति सुगम और निवेशकों के अनुकूल हो। एफडीआई को निवेशक अनुकूल बनाने के साथ यह भी कोशिश रही कि नीतिगत बाधाओं को दूर किया जाए, जो देश में निवेश प्रवाह को बाधित कर रहे थे।'' बयान के अनुसार पिछले छह साल में इस दिशा में उठाये गये कदमों के कारण ही एफडीआई में अच्छी वृद्धि हुई। मंत्रालय के अनुसार एफडीआई के मामले में नीतियों में सुधार, निवेश को सुगम बनाने तथा कारोबार सुगमता के लिये उठाये गये कदमों से देश में एफडीआई प्रवाह बढ़ा है।

छत्तीसगढ़ ने अधिशेष धान इथेनॉल संयंत्रों को देने की इजाजत मांगी

आईपीटी नेटवर्क

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों से खरीदे गए अधिशेष धान से सीधे एथेनॉल बनाने की अनुमति देने की मांग की है। राज्य सरकार का कहना है कि इससे जैव ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा धान उगाने वाले किसानों की मदद होगी। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप अधिशेष चावल से एथेनॉल उत्पादन की दर 54 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर निर्धारित करने के निर्णय के लिये धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से खरीदे गए अधिशेष धान को सीधे एथेनॉल संयत्रों को जैव ईंधन के उत्पादन के लिये सौंपे जाने की अनुमति प्रदान करने की मांग भी की है। इससे राज्य में लगने वाले एथेनॉल संयंत्रों को किसानों द्वारा सीधे धान का विक्रय किया जा सकेगा।

भारत में डिजटलीकरण वैश्विक औसत से तेजः अध्ययन

नयी दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में कंपनियां तेज गति से स्वचालन को अपना रही हैं और भारत में स्वचालन व डिजिटलीकरण अपनाने की गति वैश्विक औसत से तीव्र है। एक अध्ययन रपट में बुधवार को यह बात सामने आयी। नाकरियों पर स्वचालन के प्रभाव तथा रोबोट क्रांति के परिदृश्य पर विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के द्वारा इस अध्ययन में पाया गया कि बदलाव की गति कोविड-19 के कारण तेज हो गयी है। अध्ययन के अनुसार, भविष्य का कार्य स्वरूप समय से पहले ही आ धमका है। इसके कारण महज 26 अर्थव्यवस्थाओं में 15 उद्योगों में अगले पांच साल में 8.5 करोड़ नौकरियों पर असर पड़ सकता है। इससे मध्यम व बड़े व्यवसाय प्रभावित होने वाले हैं। अध्ययन में यह भी कहा गया कि इसके साथ ही रोबोट क्रांति से 9.7 करोड़ नयी नौकरियां भी सृजित होंगी। हालांकि इस बदलाव से अधिक जोखिम में घिरने वाले समुदायों को व्यवसायों तथा सरकारों से समर्थन की जरूरत होगी। मंच ने कहा कि नयी नौकरियां मुख्य रूप से रखरखाव (केयर) के क्षेत्र में सामने आयेंगी। ये नौकरियां चौथी औद्योगिक क्रांति के प्रौद्योगिकी उद्योगों जैसे कृत्रिम मेधा तथा सामग्री सृजन के क्षेत्रों में होंगी । अध्ययन में कहा गया, ''भारत में परिचालन वाली कंपनियों में वैश्विक औसत से ऊपर स्वचालन और डिजिटलीकरण आ रहा है। स्वचालन का वैश्विक औसत 50 प्रतिशत है, लेकिन भारत में 58 प्रतिशत कंपनियां स्वचालन अपनाने में तेजी ला रही हैं। इसी तरह कार्यों के डिजिटलीकरण पर भारत में 87 प्रतिशत कंपनियां काम रही हैं, जबकि इसका वैश्विक औसत 84 प्रतिशत है।''

बिजली बिक्री दूसरी तिमाही में 13.2 प्रतिशत बढ़ीः आईईएक्स

नयी दिल्ली। एजेंसी

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) ने बुधवार को कहा कि सितंबर तिमाही में उसकी बिजली बिक्री 13.2 प्रतिशत बढ़कर 1648.6 करोड़ यूनिट रही। बिजली मांग बढ़ने और कोविड-19 के पूर्व स्तर पर पहुंचने के साथ एक्सचेंज में बिक्री बढ़ी है। आईईएक्स ने एक बयान में कहा कि दूसरी तिमाही में औद्योगिक गतिविधियों और बिजली खपत में तीव्र वृद्धि हुई है। इसका कारण देश भर में 'लॉकडाउन' से जुड़ी पाबंदियों में ढील दिया जाना है। बयान के अनुसार एक्सचेंज में बिजली बिक्री चालू वित्त वर्ष 220-21 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 13.2 प्रतिशत बढ़कर 1648.6 करोड़ यूनिट रही। जबकि एक साल पहले 2019-20 की इसी तिमाही में यह 1,456.0 करोड़ यूनिट थी। दूसरी तिमाही में शुरू में विनिर्माण गतिविधियां धीमी रही। इसका कारण कुछ राज्यों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिये दोबारा से 'लॉकाउन' लगाया जाना था। हालांकि अगस्त और सितंबर में औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आयी। आईईएक्स ने कहा कि आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी के साथ बिजली मांग भी बढ़ी और कोविड-पूर्व स्तर पर पहुंच गयी। देश में सितंबर माह में बिजली की अधिकतम मांग में सालाना आधार पर 2 प्रतिशत और खपत में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

हिंदुस्तानी दिवाली के लिए अपने कलाकार बना रहे हैं चीन से भी बढ़िया दीये और बंदनवार

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

इस दिवाली कुछ खास होने वाली है। चीनी सामानों को मात देने के लिए इस बार भारतीय कारीगर अपने देश की मिट्टी से बढ़िया दीये और बंदनवार तैयार कर रहे हैं। इसे देश भर के बाजारों में भी भिजवाने की व्यवस्था हो रही है। दरअसल, व्यापारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स ने इस साल चीनी दिवाली मनाने के बजाय हिंदुस्तानी दिवाली मनाने का आह्वान किया है। इसी के लिए तैयारी चल रही है।

चल रही है पूरी तैयारी

कैट का कहना है कि देश भर में भारतीय सामान की आसान उपलब्धता को लेकर व्यापक तैयारी पूरी कर ली गई है। अब त्योहार से जुड़े समानों की वर्चुअल प्रदर्शनी लगाई जाएगी। देश भर के बाजारों में बने खास स्टाल्स और ऑनलाइन प्लेटफार्म के जरिये देश के प्रत्येक शहर में व्यापारिक संगठनों के माध्यम से ये सामान उपलब्ध कराए जाएंगे। कैट का कहना है कि उन्होंने दो महीने पहले से ही देश भर के व्यापारिक संगठनों को सतर्क कर दिया था। इन संगठनों ने अपने अपने क्षेत्र के कुम्हार, शिल्पकार, कारीगर, मूर्तिकार, और कलाकारों को चिन्हित कर उनसे बड़ी संख्या में दीवाली से जुड़े सामानों को बनवाना शुरू किया। इससे पहले यह देख लिया गया कि किस वस्तु की मार्किट डिमांड है। उसी के हिसाब से निर्माण कार्य कराने का निर्देश दिया गया था। अब यही व्यापारी संगठन इन सामानों को आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।

जिन्हें हम भुला चुके थे, वे बनाये जा रहे हैं

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि दीवाली से जुड़े सभी सामान जैसे दीये, मोमबत्ती, बिजली की लड़ियां, बिजली के रंग बिरंगे बल्ब, बंदनवार, घरों को सजाने के दूसरे सामान, रंगोली, शुभ-लाभ के चिन्ह, पूजन सामग्री इत्यादि सब कुछ इस बार भारतीय होगा। इसे वह कारीगर बना रहे है, जिन्हें हमने भुला दिया था। इनमें महिलाये भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। कैट देश के सबसे निचले तबके के लोगो को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश की महिलाओं के शशक्तिकरण के लिए और देश से चीनी सामानों के पूर्ण सफाये के लिए निरंतर प्रयासरत है।

खास आकर्षण

घरो के दरवाजों पर सजने वाले बंदनवार इस साल की दीवाली का मुख्य आकर्षण होंगे। पहले चीन में सस्ते सामग्रियों से बने वंदनवार भारत तो पहुंचते तो थे, पर न तो उनमें वो ताज़गी होती थी और न ही रेंज। पर इस साल ये देसी वंदनवार हर रेंज और डिज़ाइन में उपलब्ध है। ज्यादातर महिला कारीगरों के हाथों से बने ये वंदनवार 100 रुपये से शुरू हो कर 2,000 रुपये तक बिक रहे हैं। इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इनमे न सिर्फ गोटा, मोती आदि के काम किये गए है बल्कि इसमें शुभ लाभ, लक्ष्मी गणेश, कलश आदि बने हुए हैं।भारतीय दीवाली पर ये देसी वंदनवार घरो की शोभा दोगुनी करने के साथ साथ किसी गरीब कारीगर के घर को भी रौशन करने का काम करेंगे।

डिज़ाइनर देसी दीये

दीयों के बग़ैर दीवाली अधूरी रहती है। देवी लक्ष्मी के शुभ आगमन को प्रकाशित करने और घरों से नकारात्मक उर्जा को दूर भगाने के लिए दीवाली पर दीयों को खास तौर पर सजाया जाता है। और इस साल देसी कुम्हारों ने महिला कारीगरों के साथ मिल कर दीयों की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। मिट्टी से बने पारंपारिक दीयों की रेंज इस साल कुछ खास है। साथ ही अलग अलग धातुओं से बने डिज़ाइनर टी लाइट्स की एक बड़ी और आकर्षक रेंज बाज़ारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। लंबे समय से इसी व्यवसाय से जुड़ी श्रद्धा नेगी का मानना है कि देसी दीये और टी लाइट्स चीन से काफी अलग होंगे क्यों कि इनसे देश भक्ति की भावना झलकती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत, नाइजीरिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

नयी दिल्ली। एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और नाइजीरिया के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग में सहयोग को लेकर हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी प्रदान की गई। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार इस एमओयू पर जून, 2020 में बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और 13 अगस्त 2020 को अबूजा में नाइजीरिया की राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास एजेंसी (एनएएसआरडीए) ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों को सहयोग के संभावित हित क्षेत्रों जैसे पृथ्वी की सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग), सैटलाइट संचार और सैटलाइट आधारित नेविगेशन; अंतरिक्ष विज्ञान एवं ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष यान, लॉन्च व्हीकल, अंतरिक्ष प्रणालियों और जमीनी प्रणालियों का उपयोग, भू-स्थानिक उपकरण और तकनीक सहित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक अनुप्रयोग और सहयोग के अन्य क्षेत्रों को तय करने के लिए सक्षम बनाएगा। बयान के अनुसार इसके तहत एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया जायेगा, जिसमें इसरो और नाइजीरिया की राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास एजेंसी के सदस्य शामिल होंगे। संयुक्त कार्यदल समय-सीमा और कार्यान्वयन के साधनों सहित कार्य योजना को अंतिम रूप देगा। बयान में कहा गया कि भारत और नाइजीरिया लगभग एक दशक से औपचारिक अंतरिक्ष सहयोग करने के लिए प्रयासरत हैं। नाइजीरिया में भारतीय उच्चायोग की पहल के साथ, अंतरिक्ष सहयोग के लिए अंतर-सरकारी एमओयू का मसौदा विदेश मंत्रालय के माध्यम से नाइजीरियाई अधिकारियों के साथ साझा किया गया था। राजनयिक माध्यमों से विचार-विमर्श के बाद दोनों पक्षों ने समझौता ज्ञापन के एक व्यावहारिक मसौदा तैयार किया और आंतरिक अनुमोदन के लिए इसे आगे बढ़ाया। हालांकि एमओयू पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी समय से मिल गई थी लेकिन इस एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए उचित अवसर नहीं मिल पाया था क्योंकि 2019 के अंत में और इस साल की शुरुआत में कोविड -19 महामारी के कारण कुछ यात्राओं को रद्द पड़ा था।

गडकरी ने असम में रखी देश के पहले मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असम में देश के पहले मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना को राज्य के आर्थिक विकास का एक सशक्त इंजन साबित होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) इस परियोजना के पहले चरण पर 694 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके तहत जोगीघोपा में 317 एकड़ पर अगले महीने से कार्य शुरू हो जाएगा जो 2023 तक पूरा होगा। इस पार्क का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से इसका शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, " मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के आर्थिक विकास के इंजन के तौर पर काम करेगा। यह करीब 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराएगा।" इस दौरान असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह, वी. के. सिंह और रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे। कई सांसद और राज्य एवं केंद्र सरकार के अधिकारी भी इसमें मौजूद थे।

जियो प्लेटफार्म्स, क्वालकॉम ने 5जी तकनीक का सफल परीक्षण किया

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

रिलायंस जियो और अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी क्वालकॉम ने मंगलवार को कहा कि वे भारत में स्वदेशी 5जी नेटवर्क ढांचागत सुविधा और सेवाओं के तेजी से विकास तथा क्रियान्वयन के लिये मिलकर काम कर रहे हैं। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने कहा कि क्वालकॉम की प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए जियो ने देश में 5जी रैन रेडियो एक्सेस नेटवर्क विकसित किया है। इसका अमेरिका में पहले ही परीक्षण किया जा चुका है और वह सफल रहा है। क्वालकॉम के 5जी सम्मेलन में ओमान ने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि क्वालकॉम की प्रौद्योगिकी और मदद से जियो ने 5जी रैन उत्पाद विकसित किया है। इसमें एक जीबीपीएस की गति प्राप्त की गयी...।" रिलायंस जियो का यह कदम मायने रखता है। फिलहाल अमेरिका, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे कुछ ही देश 5जी ग्राहकों के लिये एक जीबीपीएस की गति उपलब्ध कराने में सक्षम है। क्वालकॉम के बयान के अनुसार क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज और रिलायंस जियो प्लेटफार्म्स अपनी पूर्ण अनुषंगी रेडिसिस के साथ मिलकर 5जी तकनीक पर काम कर रही हैं, ताकि भारत में इसे जल्द पेश किया जा सके। इस साल की शुरूआत में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घोषणा की थी कि क्वालकॉम वेंचर्स, जियो प्लेटफार्म्स में 730 करोड़ रुपये निवेश के साथ 0.15 प्रतिशत हिस्सेदारी हसिल करेगी। सौदे के तहत कंपनी ने हाल ही में राशि प्राप्त कर इक्विटी शेयर आबंटित किया है।

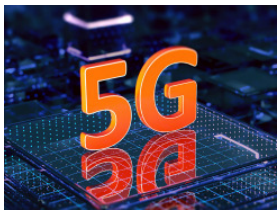

सेबी प्रमुख का धन जुटाने के लिये वित्तीय क्षेत्र की बैकिंग प्रणाली पर निर्भरता कम करने पर जोर

मुंबई। एजेंसी

सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने बुधवार को कहा कि धन जुटाने के मामले में देश के वित्तीय क्षेत्र में विविधीकरण की जरूरत है और यह बदलाव पूंजी बाजार से धन जुटाने की तरफ झुका होना चाहिए। त्यागी ने यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, "भारत में वर्तमान में वित्तीय क्षेत्र पूरी तरह से बैंक के कर्ज पर निर्भर है। इस स्थिति में विविधीकरण की जरूरत है खासतौर से बैंकिंग क्षेत्र की समस्या को देखते हुये पूंजी बाजार के जरिये धन जुटाने में सहूलियत की जानी चाहिये।" पूंजी बाजार नियामक ने चेतावनी देते हुये कहा कि जब तक बॉड बाजार को समुचित रूप से विकसित नहीं किया जायेगा तब तक 2024- 25 तक अवसंरचना क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश के सरकार के लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि भारत में इक्विटी बाजार तो काफी सक्रिय है लेकिन भारत कार्पोरेट बॉड बाजार के विकास को लेकर पिछले कई सालों से मशक्कत कर रहा है। त्यागी ने कहा कि जब तक देश में बॉड बाजार को उपयुक्त ढंग से विकसित नहीं कर लिया जाता है 2024- 25 तक देश के अवसंरचना क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य को हासिल करना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। उन्होंने कहा कि बॉड बाजार के विकास के लिये "गहरे ढांचागत और नियामकीय बदलावों" की आवश्यकता होगी। इसके लिये सरकार और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के बीच समन्वय की आवश्यकता होगी। त्यागी ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कार्पोरेट बॉड बाजार को विकसित करने के लिये कुछ कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि भारत में हर साल बॉड इक्विटी और रिण बाजार से कुल मिलाकर औसतन 9 लाख करोड़ रुपये जुटाये जाते हैं। इसमें और सुधार लाने की आवश्यकता है।

PLASTIC WASTE MANAGEMENT RULE 2016 & EXTENDED PRODUCERS' RESPONSIBILITY EXTENDED PRODUCERS' RESPONSIBILITY

व्रजेश गांधी
vrajesh@kalindimachinery.com
9425059249
kalindimachinery.in

पिछले पांच साल से लागू हुवे इस कानून में अभी भी बहुत सी चीजे ढंग से परिभाषित होना बाकी है, और इसी के चलते नाही सरकार इसे लागू कर पाई ओर नाही इसके अन्तर्गत आनेवाले इसे लागू करना चाह रहे हैयह कानून क्या है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? लगभग पूरे विश्व में एक ऐसी भावना बनाई गई की प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, क्या वास्तव में ऐसा है, अगर ऐसा है तो भी प्लास्टिक के कोई विकल्प हमारे पास है? ये सब पर्यावरण वादी सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू आम जनता को दिखा रहे है, अभी करीब जनवरी से उन सब के मुंह पर ताले पड़े है, उस की वजह ये महामारी में प्लास्टिक का एक अलग सुरक्षा कवच के रूप में उभर ना, सारे PPE KIT, मास्क इत्यादि प्लास्टिक से ही बने है, और उसी से खास कर भारत में करोड़ों लोगों की जान बचाना मुमकिन हो पाया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये महामारी का प्रकोप घटते ही ये तथाकथित पर्यावरणवादी वापस प्लास्टिक के बारे में अपना रूदाली आलाप शुरू कर देंगे, प्लास्टिक के व्यवसाय से संलग्न होने के कारण नहीं, लेकिन एक आम आदमी के हष्टिकोण से भी मेरा यकीन है कि प्लास्टिक एक वरदान स्वरूप मटेरियल है, खेर छोड़िए ये सब बातो को, हम मुद्दे कि बात पर आते हैये कानून हे क्या? 2016 मे लाए गए इस कानून का मुख्य आदेश देश म उत्पादित होने वाले कुल प्लास्टिक का रिसायकलिंग या उसका अंत, पूर्ण तरीके से होए इस लिए इसको उत्पादित करने वाले सं थान या ये जिस के लिए उत्पादित हो रहा है उन लोगो को इसके लिए जवाबदार बनाया जाय, इसमें ब्रांड मालिक (जो अपने उत्पाद को बेचने के लिए प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल का इस्तेमाल करता हो) प्रोड्यूसर (प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल बनाने वाले) ओर इंपोर्टर (प्लास्टिक का पैकेजिंग मटेरियल या उसको बनाने में काम आने वाले मटेरियल को इंपोर्ट करने वाला) को जवाबदार माना गया हैंअभी ये कानून में केरीबेग, पाउच ओर अन्य पैकिंग मटेरियल को ही इसके दायरे में रखा है, मतलब प्लास्टिक के अन्य उत्पाद जैसे पाईप, एसेसरीज में लगने वाला प्लास्टिक इत्यादि को इससे बाहर रखा गया है, दुनियाभर के देशो मे ऐसे कानून काफी पहले से है, लेकिन हमारे देश का मसला ही अलग है, यहां किसी को किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार बनाना शायद काफी मुश्किल है, यह कानून कहता है कि सभी ब्रांड के मालिक कंपनी या व्यक्ति अगर अपने किसी भी उत्पाद के पैकिंग के लिए प्लास्टिक का इस्तमाल कर रहा है तो उस ब्रांड के मालिक को, सरकार के पॉल्युशन कंट्रोल विभाग में अपना पंजीकरण कराना होगा, अगर ये ब्रांड के मालिक एक या दो राज्य में अपना कारोबार करते है तो उन्होंने एक या दो राज्यो के पॉल्युशन कंट्रोल विभाग में अपना पंजीकरण करना होगा, ओर अगर कारोबार दो से ज्यादा राज्यो मे हे तो सेंट्रल पॉल्युशन कंटोल विभाग में अपना पंजीकरण करना होगा, एक बार पंजीकरण होने के बाद, इस ब्रांड मालिकों को अपने उत्पाद के पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक की मात्रा के बराबर वैसे ही प्लास्टिक को रीसायकल करना होगा ओर जो रीसायकल नहीं हो सकता उस उसके अंतिम पड़ाव तक पहुंचना होगा।

इस बात को एक आसान नमूने से समझते है

एक कंपनी है 'XYZ नमकीन' यह कंपनी देश के 6 राज्यो में अपना कारोबार करती है, ओर उसकी चार राज्यों में उत्पादन इकाई हे तो उसे एक मात्र पंजीयन सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल विभाग में करना होगा, अब रजिस्ट्रेशन हो गया, ओर कंपनी अपने उत्पादों के पैकिंग के लिए हर महीने, 500 किलो प्लास्टिक इस्तमाल करती है, तो XYZ कंपनी को वैसा ही (अगर PP है तो PP अगर PVC है तो इन्न और अगर MLP है तो MLP) 500 किलो प्लास्टिक को रीसायकल करना हे या रीसायकल ना हो पाने वाले प्लास्टिक को उसके अंत तक पहुंचना हे, याने सीमेंट प्लांट में उस ईंधन के रूप में या सड़क बनाने इत्यादि मे इस्तेमाल करना है, ओर हर राज्यो में बेची गई मात्रा के बराबर मात्रा में प्लास्टिक उस राज्यों से इकठ्ठा कर ये गतिविधि को अंजाम देना है, अगर XYZ कंपनी 500 किलो में से MP में 80 किलो, CG में 20 किलो, महाराष्ट मे 160 किलो, गुजरात में 90 किलो, ओर UP मे 150 किलो पैकेजिंग मटेरियल मे अपना उत्पाद बेचता है तो उसे इस राज्यो से इतनी ही मात्रा में उपयोग किया हुआ प्लास्टिक इकठ्ठा कर उसे रीसायकल करना है या रीसायकल ना हो पाने वाले प्लास्टिक को उसके अंत तक पहुंचना है। ये पैकेजिंग मे बड़ा हिस्सा तो उसके पाउच का होगा लेकिन इसके अलावा सेकंडरी पैकिंग में इस्तेमाल हवे प्लास्टिक के बोरे, अगर कार्टन मे सेकंडरी पैकिंग हे तो उसको बंध करने में इस्तमाल की BOPP टेप, ये सब कुल पैकिंग मटेरियल 500किलो मे शामिल होता है।

अब ये प्रक्रिया पूरा करने को take back plan कहते है, वो ब्रांड मालिक या तो खुद ये करे या कोई एजेंसी जिसे PRO कहते है, उससे करवाए

अब में प्लास्टिक व्यवसाई की बात पर आता हं, जैसा कि मेने आगे बताया, इस कानून में ब्रांड मालिक के साथ प्रोड्यूसर ओर इंपोर्टर को भी इसके लिए जिम्मेदार माना है, अब सोचिए अगर A कंपनी पाउच बनाने वाली प्रोड्यूसर कंपनी है ओर उसने XYZ कंपनी को 450 किलो प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल बेचा, XYZ कंपनी ने 40 किलो वूवन सेक् थैले B कंपनी से ओर करीब 10 किलो जितनी BOPP टेप C कंपनी से खरीदी, जैसा कि हमने पहले देखा XYZ कंपनी ने वो 500 किलो के लिए take back की प्रक्रिया कर ली हे तो फिर वोही 500 किलो का फिर से take back क्यों हो? इस कार्य में A - B - C और XYZ कंपनी आर्थिक जिम्मेदारी तो बांट सकते हे लेकिन एक ही मटेरियल का दो बार take back करने की जरूरत कतई नहीं है। आशा करता हूं ये कानून की जटिलता अब आपके समझ में आ गई होगी, अब प्लास्टिक प्रोड्यूसर ओर इंपोटर के लिए एक महत्व पूर्ण बात, उन्हें ये कानून के अंतर्गत अपना पंजीयन तो करना है, उन्हें ब्रांड मालिक का आर्थिक सहयोग भी करना चाहिए, लेकिन उसी मटेरियल के लिए दुबारा take back करना नहीं है, तो अगर वो जितना मटेरियल ब्रांड मालिको को बेचता हे उसकी take back की जवाबदारी से वह मुक्त है, हा उसे मटेरियल बेचते समय इनवॉइस पर ब्रांड मालिक का पंजीयन क्रमांक लिखना आवश्यक होगा, तो प्रोड्यूसर या इंपोर्टर सिर्फ वो ही मटेरियल के take back के लिए जवाबदार है जो उसने बिना पंजीयन वाले ग्राहक को बेचा है। मेरा सभी प्लास्टिक निर्माता और इंपोर्टर से निवेदन है कि जब ये कानून आही गया है तो उससे बिना डरे उसके उचित क्रियान्वयन के लिए अपने आप को ओर अपने ग्राहकों को तैयार करेंमेने ये सब बातो को हो सके उतना सहज भाषा में समझाने कि कोशिश की है, आशा करता हूं आप पसंद करेंगेआप इस कानून के बारे में आनेवाली किसी भी प्रकार की समस्या के हल के लिए मुझे संपर्क कर सकते है।

वर्ल्ड फूड डे पर, सेहतमंद रहने के लिये बादाम खाएं!

नई दिल्ली। एजेंसी

भूखे रहने वाले लोगों के लिए वैश्विक जागरूकता एवं कार्यवाही को बढ़ावा देने और सेहतमंद डाइट सुनिश्चित करने की जरूरत को रेखांकित करने के लिये हर साल वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। इस साल का थीम सभी के लिये स्थायी भविष्य के निर्माण पर केन्द्रित है और दुनियाभर के लोग सभी के लिये खाद्य सुरक्षा और पोषक आहार सुनिश्चित करने की जरूरत को प्रकाश में लाने के लिये एक साथ होंगे। भोजन जीवन का सार है और हमारी संस्कृतियों और समुदायों की जड़ भी। इस कठिन समय में, जब दुनिया एक महामारी का सामना कर रही है, तो सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक पहुँच जरूरी है। इसमें हम सभी की भूमिका होगी, कम से कम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाले आहार लेने के मामले में। हमें स्वस्थ रहने की कोशिश करनी चाहिये और अच्छा पोषण सुनिश्चित करना चाहिये। इसकी शुरूआत का अच्छा तरीका है खाने की चीजों को सोच-समझकर चुनना और बादाम जैसे सेहतमंद स्नैक्स खाना। बादाम में कई पोषक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन 'ई', मैग्नीशियम, रिबोफ्लेविन और जिंक, जो हेल्दी डाइट और

लाइफस्टाइल में योगदान देते हैं।

मैक्स हेल्थकेयर, दिल्ली में डायटेटिक्स की रीजनल हेड ऋतिका समद्दर ने कहा, साल 2020 में मौजूदा महामारी के कारण अधिकांश परिवार अपना ज्यादातर समय घर में बिता रहे हैं, जिससे लाइफस्टाइल में आलस आ गया है। आलस वाली लाइफस्टाइल में डिजिटल पर ज्यादा निर्भरता, ज्यादा स्क्रीन टाइम, भोजन करने में अनियमितता, कसरत और एक्टिविटी की कमी और अनहेल्दी स्नैक्स ज्यादा मात्रा में लेना शामिल है। इस उल्टे चक्र को तोड़ने के लिये कैलोरी से भरे स्नैक्स खाना छोड़ें और बादाम, ताजे मौसमी फल और दही जैसे पोषक स्नैक्स लें। खासकर बादाम जैसे हेल्दील स्नैक को चुनें जिनमें कई पोषक-तत्व होते हैं और वे कई लाभ देते हैं, जैसे वजन पर नियंत्रण, हृदय का स्वास्थ्य, डायबिटीज पर नियंत्रण और त्वचा का स्वास्थ्य। बादाम के साथ स्मार्ट तरीके से स्नैकिंग करना एक छोटा, लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव होगा, जो आपके लाइफस्टाइल को सेहतमंद बना देगा।'' फिटनेस एक्सपर्ट और सेलेब्रिटी मास्टर इंस्ट्रक्टर यास्मीन कराचीवाला के अनुसार, जिन्दगी कितनी भी व्यस्त और तनावपूर्ण क्यों न हो, अपनी हेल्थ और फिटनेस से समझौता कभी नहीं करना चाहिये। चुनौती कुछ भी हो, दिन में कम से कम 30 मिनट कसरत जरूर करें। अपने वर्कआउट रूटीन को अच्छी स्नैकिंग से संपूर्ण बनायें, इससे वजन पर भी बेहतर नियंत्रण मिलेगा।

हर भारतीय को स्वस्थ बनाने का वादा झंडु का

कोलकाता। आईपीटी नेटवर्क

भारत में, एफएमसीजी क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी, इमामी लिमिटेड के स्वामित्व में, एक सदी पुराने आयुर्वेदिक ब्रैंड, झंडु ने 'इम्यून इंडिया ऑफर' लॉन्च किया है, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में, देश का साथ देने का प्रयास करते हुए, इस मुश्किल समय में, झंडु ने, हर भारतीय में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और व्यक्तिगत स्वच्छता की अच्छी आदत डालने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए, झंडु ने 'इम्यून इंडिया ऑफर' नामक, एक अनोखा ऑफर लॉन्च किया है। इसके तहत झंडु च्यवनप्राश, उस स्पेशल प्राइस पर लॉन्च किया गया, जिस कीमत पर पहले कभी इसकी बिक्री नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, अब झंडु च्यवनप्राश के हर पैक के साथ झंडु आयुर्वेदिक सैनेटाइज़र भी मुफ्त दिया जा रहा है। इमामी लिमिटेड के डायरेक्टर श्री हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा कि 'शेष दुनिया के साथ, हम एक अभूतपूर्व मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। इस समय दो चीजें हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना। भारत सरकार के केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश खाने की सिफारिश की है। हम भी ,झंडु की 100 वर्षों की आयुर्वेदिक विरासत और ज्ञान का लाभ सर्वश्रेष्ठ ढंग से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। झंडु च्यवनप्राश का 900 ग्राम का पैक अब 100 रुपये की छूट के साथ मिल रहा है। इसके साथ इम्यून इंडिया ऑफर के तहत झंडु आयुर्वेदिक सैनेटाइज़र मुफ्त दिया जा रहा है। महामारी के खिलाफ राष्ट्र का सहयोग कर, हमें अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। हमारा मानना है कि हर भारतीय के शरीर की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए, यह पूरी तरह से उसकी जेब पर फिट बैठने वाला 'अफोर्डेबल कॉम्बो है।' आयुर्वेद सार संग्रह के निर्देशानुसार निर्मित झंडु च्यवनप्राश में 39 बेशकीमती आयुर्वेदिक जड़ीबूटियों का बेहद शानदार मिश्रण है, जिसमें आँवला, गिलोय और अश्वगंधा शामिल हैं। वैज्ञानिक रूप से यह प्रमाणित हो चुका है कि इसमें दोगुनी रोग प्रतिरोधक शक्ति है। यह लैब में एनके (नेचुरल किलर) सेल एक्टिविटी से लैस है। झंडु च्यवनप्राश, सर्दी खाँसी जैसी बीमारियों से हमें सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। क्वॉलिटी कंट्रोल के उच्च मानकों के तहत हर सुबह दूध या शहद के साथ झंडु च्यवनप्राश लेने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार आता है। इससे रोजाना की जिंदगी में ज्यादा ऊर्जा और स्टेमिना से अपना काम करने की शक्ति मिलती है।

शारदीय नवरात्र विशेष

आस्था-पर्व

आर.सी.शर्मा

इस साल सभी लोगों का अभी तक का अधिकतम समय कोरोना के कहर के कारण हताशा और निराशा में ही गुजरा है। इसकी दहशत लगातार जारी है। ऐसे संकट से उबारने के लिए हम सबको इस शारदीय नवरात्र में संकट-हरणी मां आदिशक्ति की उपासना श्रद्धा-भक्ति के साथ अवश्य करनी चाहिए।

जगत के कष्ट हरो हे मां शक्तिस्वरूपा

अभी कल से ही शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हुआ है। वैसे तो हर वर्ष श्रद्धालुओं को मां शक्तिस्वरूपा के इन पावन दिनों का बेसब्री से इंतजार रहता है लेकिन इस बार यह इंतजार और भी घनीभूत हो गया था। कारण, बीते कई माह से संपूर्ण देश ही नहीं अपितु विश्व को कोरोना महामारी की काली छाया ने भयाक्रांत कर रखा है। ऐसे में सभी इस नवरात्र में मां दुर्गा से संकट को हरने की प्रार्थना कर रहे हैं। सभी को भरोसा है कि अपने भक्तों की पुकार सुनने वाली मां, संपूर्ण मानवता पर मंडराते इस संकट से भी अवश्य मुक्त कराएंगी।

जीवन में नई स्फूर्ति का संचार

शारदीय नवरात्र के ये पुण्यकारी दिन, भारतीय जनमानस के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। इन पावन दिनों के आगमन से जीवन की हताशा, निराशा छंटने लगती है और जीवन में नई उमंग, नई स्फूर्ति का संचार होने लगता है। शारदीय नवरात्र से ही पर्वों की लंबी श्रंखला भी शुरू होती है, जो आगे चलकर शीत ऋतु के बाद वसंत ऋतु से जुड़ती है। इस दौरान बारिश के दिन खत्म हो चुके होते हैं। रबी की फसल की बुआई के लिए जोर-शोर से तैयारियां हो रही होती हैं। बारिश के दिनों में जो हर तरफ बेतरतीबी छा गई थी, वो सब करीने से कांट-छांट दी जाती है। चारों तरफ कुदरत सजी-संवरी हुई दिखने लगती है। मां शक्ति की पूजा के साथ ही कई पर्व आते हैं। इस तरह देखा जाए तो भारतीय जीवन में शारदीय नवरात्र मानसून की अस्त-व्यस्तता, उदासीनता और ठहराव को पीछे छोड़कर नई उमंग, नई स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ने का समय है।

नौ दिन होती है देवी पूजा

शारदीय नवरात्र का आरंभ आश्विन मास में शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है, जो इस साल 17 अक्टूबर को थी। हालांकि हर वर्ष पितृपक्ष के तुरंत बाद नवरात्र शुरू हो जाते हैं, लेकिन यह साल मलमास या अधिमास था, इस वजह से पिछले महीने पितृपक्ष खत्म होने के ठीक एक महीने बाद कल यानी 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू हुए। इस दिन विधि-विधान से घट स्थापित करने के बाद अगले नौ दिन तक कुलदेवी के समक्ष मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। अब 24 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी और महानवमी मनाए जाने के बाद 25 अक्टूबर को विजयदशमी या दशहरा पर्व के रूप में इनका समापन होगा। इस दौरान श्रद्धालुजन प्रतिदिन मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों की आराधना करेंगे।

इस बार की महत्ता है अधिक

चूंकि यह साल कोरोना की दहशत का साल है, भले अब तक पांच चरणों में लॉकडाउन खुल चुका हो, लेकिन अभी लोगों के दिलों-दिमाग में कोरोना को लेकर भय व्याप्त है। इसलिए इस बार शारदीय नवरात्र का महत्व बीते सालों से कहीं ज्यादा है। इस नवरात्र में आम लोगों को मां शक्ति से मनोबल मिलेगा, नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति का संचार होगा और निश्चित रूप से इस सबका असर कोरोना से लड़ी जा रही लड़ाई पर पड़ेगा। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन मनोविज्ञान के आईने में देखें तो इस बार हमें मां शक्ति से मिलने वाले मनोबल की ज्यादा आवश्यकता है। *

राशि अनुसार करें पूजन

यूं तो कोई भी भक्त इस पूजा को अपनी आस्था के अनुसार कर सकता है, लेकिन ज्योतिषशास्त्र के अनुसार भक्तों को अपनी राशि के अनुसार मां दुर्गा की पूजा करना अधिक फलदायी होता है। लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि वह अपनी राशि के मुताबिक किस तरह मां शक्तिस्वरूपा की पूजा करें। मेष राशि वाले जातकों को मां स्कंदमाता की विशेष पूजा करनी चाहिए। वृषभ राशि वालों को मां महागौरी के स्वरूप की पूजा करना ज्यादा फलदायी होगा। जिन लोगों की राशि मिथुन हो वे मां ब्रह्मचारिणी की, जिनकी कर्क राशि हो वे मां शैलपुत्री और जिनकी सिंह राशि हो, उन्हें मां कूष्मांडा की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। जिनकी कन्या राशि हो, उन्हें भी मां ब्रह्मचारिणी और जिनकी तुला राशि हो, उन्हें मां महागौरी और जिनकी वृश्चिक राशि हो, उन्हें स्कंदमाता तथा धनु राशि वालों को मां चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। मकर राशि वाले मां कालरात्रि की पूजा करें तो कुंभ राशि वालों के लिए मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना तथा मीन राशि वालों को भी मां चंद्रघंटा की पूजा करना अधिक कल्याणकारी हो सकता है। *

कविता

अलका 'सोनी'

देवी जागो

इस जगत में
सृष्टि के कण-कण में
हो समाई तुम
देवी अब तो जागो।
हारा है विश्व
कराहा है विश्व
सुबकती दिखती है
यह धरती
सजल नयन
है मूक गगन
हे प्राणशक्ति
अब तो जागो।
बंद विद्यालय और
सूने प्रांगण
चहक उठे जब फिर से
भोर आए वो
अब मनभावन
ओ वीणापाणि जागो।
माया से ही रचित विश्व
माया से ही चलित विश्व
माया कर्तव्य
माया ही दृश्य
हे महामाया जागो।
हरी-भरी रहे यह धरती
कहीं न हो यह परती
हे सुजलाम-सुफलाम
वरदायिनी शक्ति जागो।

सोनी इंडिया ने भारत में पहला 8K टेलीविजन Z8H लांच किया

नयी दिल्ली। घर में सर्वोत्तम सिनेमा अनुभव के लिए सोनी इंडिया ने भारत में पहला 8K टेलीविजन Z8H लांच किया। नया Z8H प्रीमियम व्यूइंग अनुभव प्रदान करता है और असाधारण ज़बरदस्त पिक्चर क्वॉलिटी, बेमिसाल कलर, कांट्रास्ट, और क्लैरिटी फुल एरे LED के साथ प्रदान करता है। 8ख के साथ अब बड़ी स्क्रीन की मंत्रमुग्ध कर देने वाली दुनिया में कदम रखें, जहां एब्सोल्यूट ब्लैक्स के साथ इमेजेस एकदम जीवंत हो उठती हैं और X-वाइड एंगल के साथ पूरी बारीकियों वाला सुपर-वाइड व्यूइंग एंगल मिलता है। एक मिनिमलिस्ट वन-स्लेट डिज़ाइन और पतले बेज़ल वाला यह 8K LED TV सबसे ताकतवर पिक्चर प्रोसेसर X1रू अल्टिमेट के साथ बड़ी स्क्रीन वाले 8K अनुभव को आपके घर लाता है जो 8K TV की भरपूर डेप्थ और बारीकियों से सुसज्जित है। यह स्मार्ट एंड्रायड TV PS5 रेडी है।

216 सेमी (85) में उपलब्ध नया Z8H भरपूर डेप्थ और बारीकियों को असाधारण रेजोल्यूशन के साथ पेश करता है और 4K TV के मुकाबले 4 गुने ज्यादा पिक्सेल्स के साथ एकदम असली दुनिया की जीवंत तस्वीरों को आपके सामने उत्पन्न करता है। Z8H में 8K के साथ लाइफलाइक इमेज और बेजोड़ असली आनंद का अनुभव प्राप्त करें। यह किसी भी तरह के कंटेंट को सोनी की अद्वितीय खूबियों के साथ लाइफलाइक 8K रेजोल्यूशन में बदल देता है।

सोनी के ताकतवर प्रोसेसर के साथ किसी भी तरह के कंटेंट को लाइफलाइक 8K रेजोल्यूशन में बदला जा सकता है, आप चाहे कुछ भी देख रहे हों। X1रू अल्टिमेट, पिक्चर प्रोसेसर, डाटा का सटीकता से विश्लेषण और प्रोसेस करके 4K की तुलना में चार गुने रेजोल्यूशन के साथ 8K पिक्चर्स प्रस्तुत करता है, जो डेप्थ, टेक्सचर, और बारीकियों से भरपूर होते हैं। 4K और 2K में फिल्माई गई इमेज भी 8K X-रियलिटीरू प्रो द्वारा एक अद्वितीय 8K डाटाबेस का उपयोग करते हुए 8K तक अपस्केल कर दी जाती है। फिर प्रत्येक सब्जेक्ट का रेजोल्यूशन ऑब्जेक्ट-बेस्ड सुपर रेजोल्यूशन द्वारा ऑप्टिमाइज करके ज्यादा डेप्थ, टेक्सचर, और ज्यादा वास्तविक पिक्चर टेक्सचर निर्मित किए जाते हैं। जहां ज्यादातर TV में केवल कांट्रास्ट को ही एक ब्लैक-टू-व्हाइट कांट्रास्ट कर्व के साथ एडजस्ट किया जाता है, वहीं इसमें ऑब्जेक्ट-बेस्ड HDR रिमास्टर के साथ स्क्रीन पर अलग-अलग ऑब्जेक्स के कलर्स का विश्लेषण किया जाता है और फिर कांट्रास्ट को एडजस्ट किया जाता है।

चेन्नई में प्याज 73 रुपये प्रति किलोग्राम पर, महानगरों में सबसे महंगी

नयी दिल्ली। एजेंसी

चेन्नई के खुदरा बाजार में प्याज की कीमतें मंगलवार को 73 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। यह दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में प्याज का सबसे महंगा दाम है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस संबंध में आंकड़े जारी किए हैं। प्याज की कीमतें बढ़ने की वजह उत्पादक क्षेत्रों में बारिश होने से आपूर्ति बाधित होना है। आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली में प्याज का खुदरा भाव 51 रुपये प्रति किलोग्राम, कोलकाता में 65 रुपये प्रति किलोग्राम और मुंबई में 67 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। विशेषज्ञों और व्यापारियों का मानना है कि दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रों में भारी वर्षा से आपूर्ति बाधित हुई है और इससे खरीफ की फसल की आवक प्रभावित हुई है। यह आपूर्ति आने वाले हफ्तों में पूरी तरह से बहाल होने का अनुमान है। फिलहाल रबी फसल के दौरान एकत्रित प्याज बाजार में बेचा जा रहा है। आम तौर पर खपत वाले क्षेत्रों में कीमतें इस दौरान बढ़ जाती हैं, लेकिन प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में बारिश ने तबाही मचा दी है, जिससे आपूर्ति में कमी आई है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चेन्नई में प्याज की कीमतें तेजी से बढ़कर 73 रुपये प्रति किलोग्राम रही, जबकि एक साल पहले यह कीमत 33 रुपये प्रति किलोग्राम थी। मुंबई में भी प्याज की कीमत पिछले साल के 56 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर अब 67 रुपये प्रति किलोग्राम रही। जबकि कोलकाता में यह कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 65 रुपये प्रति किलोग्राम हो गयी। दिल्ली में कीमतें एक साल पहले की समान अवधि में 46 रुपये प्रति किलोग्राम थी जो अब बढ़कर 51 रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं है। देश में प्याज के शीर्ष उत्पादक क्षेत्र महाराष्ट्र के नासिक में भी प्याज का खुदरा मूल्य मंगलवार को 66 रुपये प्रति किलोग्राम रहा, जो एक साल पहले की समान अवधि में 35 रुपये प्रति किलोग्राम था। प्याज की घरेलू उपलब्धता और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पिछले महीने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

लक्जरी ऑल-राउंडर ऑडी क्यू2 भारत में

मुंबई। जर्मन लक्जरी कार विनिर्माता ऑडी ने भारत में अपनी स्पोर्टी ऑल-राउंडर ऑडी क्यू2 लांच करने की घोषणा की है। रोज़ाना की ड्राइविंग और ऐडवेंचर ट्रिप दोनों के लिए उपयोगी ऑडी क्यू2 एक लक्जरी ऑल राउंडर है। इसका बोल्ड डिजाइन, साथ में प्रभावशाली कट्स और क्रीज़ युवा और प्रगतिशील ग्राहकों को खूब भाएंगे जो अपनी पसंद के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। स्पोर्टिंग फीचर आम तौर पर इस से एक दर्जे ऊपर के लिए होता है किंतु ऑडी क्यू2 में रु। 34ए99ए000 की कीमत पर ये आपको मिल रहे हैं। इस लांच पर ऑडी इंडिया के प्रमुख श्री बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा, ऑडी क्यू2 एक ऐसी कार है जिसे भारत में प्रस्तुत करते हुए हम बहुत ही ज्यादा रोमांचित हैं। हमने ग्राहकों की मांग को सुना और हम इस विलक्षण किंतु व्यावहारिक ऑडी क्यू2 को त्योहारों के मौसम में लेकर आए हैं। इसका अनूठा डिजाइन, आलीशान इंटीरियर और इसके अनेकानेक फीचर्स तो इसकी अपील का एक ही हिस्सा हैं। मैंने खुद इसे बहुत चलाया है और मैं कह सकता हूं कि ऑडी क्यू2 एक बेहद रोमांचक ड्राइव है। इसका 190एचपी, 2।0 लीटर टीएफएसआई इंजन, प्रगति'शील स्टीयरिंग और क्वात्रो हर एक ड्राइव को जो'श से भरपूर बना देते हैं।'' ऑडी क्यू2 को हर जरूरत को पूरा करने और कहीं पर भी घर जैसा आराम महसूस कराने के लिए इंजीनियर किया गया है, चाहे आप 'शहर में घूम रहे हों या 'शहर से दूर। यह कार 2।0 लीटर टीएफएसआई पैट्रोल इंजन से 'शक्ति प्राप्त करती है जो 190एचपी की ताकत उत्पन्न करता है। प्रगति'शील स्टीयरिंग, क्वात्रो ऑल-व्हील ड्राइव और स्पोर्टी आयामों से युक्त यह कार बेहतरीन ड्राइविंग डायनमिक्स मुहैया कराती है और ऐसा हो पाता है ऑडी ड्राइव सिलेक्ट की वजह से, आप अपनी पसंद के मुताबिक ड्राइविंग अनुभव को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।

बर्जर पेंट्स ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए आईआईटी गुवाहाटी से गठबंधन किया

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

जब देश सब कुछ सामान्यी होने की तैयारी में जुटा है, भारत में पेंट्स की प्रमुख कंपनी बर्जर पेंट्स ने ब्रीथईजी सेफ 24 और मल्टी सरफेस प्रोटेक्टर को लॉन्चत करने की घोषणा की है। यह कीटाणुओं, बैक्टीरिया और कोविड जैसे वायरस से 24 घंटे सुरक्षा करता है। नैनो सिल्वर तकनीक पर डिजाइन किया गया यह प्रॉडक्ट अल्कोहल फ्री और एनवॉयरमेंट फ्रेंडली है।

जब देश में कोविड महामारी का हमला हुआ था तो सरकार चाहती थी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और कॉरपोरेट्स कोरोना वायरस महामारी से जंग के लिए कुछ नए समाधान के साथ सामने आएं। पिछले कुछ महीनों से भारत ने नए-नए प्रॉडक्ट्स को लॉन्चछ कर इस राह में नेतृत्व की दिशा में कदम उठाया है। ब्रीथ ईजी सेफ 24 इसी सफर में एक क्रांतिकारी कदम है।

बर्जर पेंट्स के एमडी और सीईओ श्री अभिजीत रॉय ने लॉन्चिंग के मौके पर उत्साहित होते हुए कहा, बर्जर पेंट्स उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए-नए प्रॉडक्ट्स के निर्माण में हमेशा से आगे रहा है। सेफ 24 हमारी

इनोवेशन के मूलभूत सिद्धांत का एक अन्य गवाह रहा है। आर्थिक गतिविधियों के धीरे-धीरे बढ़ने से अब ऐसे प्रॉडक्ट्स की मांग बढ़ रही थी, जो लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करें। गुवाहाटी के प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आइआइटी-जी) की तकनीक भारतीय उपभोक्तादओं तक पहुंचाने में हमें काफी प्रसन्नता हो रही है क्योंकि इसने बहुत बड़ी जरूरत का अंतर भरा है। हमें भरोसा है कि संकट की इस घड़ी में सेफ 24 लोगों और सरकार के लिए काफी मददगार साबित होगा।

इस प्रोजेक्ट को गुवाहाटी आईआईटी के वैज्ञानिकों ने प्रोफेसर बिमान बी। मंडल के नेतृत्व में विकसित किया था। इस मौके पर प्रोफेसर मंडल ने कहा, सेफ 24 नॉर्मल अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से काफी अलग है क्योंकि यह किसी सतह पर काफी लंबे समय तक सक्रिय रहता है। इसमें एक सुरक्षात्मक नैनो कवर कोटिंग रहती है, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार बैक्टीरिया और वायरस से लंबे संमय तक जंग लड़ता है। आईआईटी गुवाहाटी ने कोविड से लड़ाई लड़ने में देश और समाज की मदद करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स डिजाइन करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। हम आशा करते हैं कि मुसीबत के इस समय में यह प्रोजेक्ट्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सुरक्षित तो बनाएगा ही। यह हमें पूरी सुरक्षा भी प्रदान करेगा।

सरकार 30.67 लाख कर्मचारियों को देगी 3,737 करोड़ रुपये का बोनस

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिये उत्पादकता आधारित बोनस और तदर्थ बोनस की घोषणा कर रही है। इसे जल्दी संबंधित कर्मचारियों को दिया जाएगा।'' बयान के अनुसार, '' उत्पादकता से संबद्ध बोनस के तहत भारतीय रेल, डाक, रक्षा, ईपीएफओ और ईएसआईसी समेत अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के 16.97 लाख गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इससे सरकार पर 2,791 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा।'' इसमें कहा गया है, ''गैर-उत्पादकता से जुड़ा बोनस या तदर्थ बोनस केंद्र सरकार के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है। इससे 13.70 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इससे सरकार पर 946 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा।'' इस प्रकार, कुल 30.67 लाख कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा और सरकार पर कुल 3737 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा।

कृत्रिम मेधा, डिजिटल वित्तीय सेवाएं समेत 20 बाजार ला सकते हैं अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव: डब्ल्यूईएफ

नयी दिल्ली। एजेंसी

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने बुधवार को शिक्षा प्रौद्योगिकी और कौशल विकास सेवा, कृत्रिम मेधा, डिजिटल वित्तीय सेवाएं जैसे भविष्य की 20 बाजारों की सूची जारी की जो अर्थव्यवस्थाओं में समावेशी और टिकाऊ रूप से बदलाव ला सकते हैं। मंच ने भारत को उन देशों के साथ रखा है जहां फिलहाल इस प्रकार के बदलाव को लेकर मजबूत प्रौद्योगिकीय व्यवस्था है। जिनेवा के इस संगठन ने 'जॉब री-सेट' (रोजगार बदलाव) विषय पर आयोजित ऑनलाइन सम्मेलन में श्वेत पत्र जारी करते हुए यह भी कहा कि भारत समेत कई देशों को इन बाजारों को आगे ले जाने के लिये सामाजिक और संस्थागत ताने-बाने को विकसित करने की जरूरत होगी। कल यानी भविष्य की इन बाजारों की सूची में कृत्रिम मेधा, शिक्षा प्रौद्योगिकी और कौशल विकास सेवा, अंतरिक्ष यात्राएं, जीन और डीएनए अनुक्रम, बीमारी के इलाज और उसकी रोकथाम के लिये उभरता नया रुख (प्रीसिशन मेडिसिन) और दुर्लभ बीमारियों को ठीक करने से जुड़ी दवाएं, उपग्रह सेवा, ग्रीनहाउस गैस भत्ता, पुनःवनीकरण सेवाएं और हाइड्रोजन को रखा गया हैं। इसके अलावा सूची में इलेक्ट्रिक वाहन, प्लास्टिक पुनर्चक्रण, डेटा, हरइपरलूप आधारित परिवहन सेवाएं, डिजिटल वित्तीय सेवाएं, बेरोजगारी बीमा आदि को जगह दी गयी हैं। मंच ने कहा कि इनमें से कुछ बाजार विशेष रूप से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर निर्भर

करेंगी जबकि अन्य के लिये नये सामाजिक और संस्थागत ढांचे की जरूर होगी। कुछ बाजारों में दोनों तत्व मिले-जुले रूप में होंगे। डब्ल्यूईएफ ने कहा कि ये बाजार समाज के संरक्षण और लोगों को सशक्त बनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार हो सकते हैं। मंच ने कहा कि जिन देशों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ मजबूत सामाजिक पूंजी और भविष्योन्मुख संस्थानें हैं, वे आर्थिक बदलाव के लिये जरूरी इस बाजारों को बेहतर तरीके से सृजित कर सकते हैं। डब्ल्यूईएफ ने कहा, "इस समय दुनिया कोविड-19 महामारी के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव से जूझ रही है। ऐसे में नई अर्थव्यवस्था को आकार देने की मांग बढ़ रही है जो व्यापक रूप से सामाजिक और पर्यावरण चुनौतियों का समाधान करने के साथ आर्थिक वृद्धि सृजित कर सके।" मंच ने कहा, "इसे हासिल करने और नये बाजारों को संबल देने के लिये दुनिया को प्रौद्योगिकी और सामाजिक-संस्थागत नवप्रवर्तन का महत्वकांक्षी एजेंडा तय करने की जरूरत है। इसी से इन चुनौतियों के समाधान में मदद मिल सकती है।" डब्ल्यूईएफ की रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की क्षमता है, मजबूत सामाजिक पूंजी और भविष्योन्मुख संस्थाएं हैं, वे संभवतः नये बाजारों के विकास में सफल होंगे। इस लिहाज से नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, डेनमार्क, जर्मनी और नार्वे के पास सामाजिक-संस्थागत नवप्रवर्तन की काफी क्षमता है। वहीं जापान, जर्मनी, अमेरिका, कोरिया गणराज्य और फ्रांस में प्रौद्योगिकीय विकास के मामले में सर्वाधिक संभावना है। डब्ल्यूईएफ ने कहा कि ज्यादातर विकसित अर्थव्यस्थाएं इन दोनों मामले में अच्छी स्थिति में हैं। कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाएं चेक गणराज्य, इस्त्र, इटली, जापान और स्पेन के साथ ब्रिक देशों (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) तथा कुछ अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं (हंगरी और पोलैंड) में इस प्रकार के बाजारों के लिये मजबूत प्रौद्योगिकीय व्यवस्था है लेकिन उन्हें सामाजिक और संस्थागत ताना-बाना विकसित करने की जरूरत होगी। रिपोर्ट के अनुसार भारत, स्पेन और जापान सामाजिक-संस्थागत नवप्रवर्तन के मामले में तय मानदंड से थोड़े नीचे हैं जबकि ताइवान, चीन की अर्थव्यवस्थाएं उससे ऊपर हैं।

स्वीडन ने चीन को बड़ा खतरा बताते हुए दिया झटका

5जी के लिए हुवावेई और जेडटीई पर लगाया बैन

स्टॉकहोम। एजेंसी

स्वीडन ने चीन को देश के सबसे बड़े खतरों में से एक बताते हुए 5जी प्रौद्योगिकी के लिए चीनी कंपनी हुवावेई और जेडटीई के नेटवर्क-उपकरणों के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश के दूरसंचार नियामक ने मंगलवार को कहा कि 5जी प्रौद्योगिकी के लिए होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेने वाली चार दूरसंचार कंपनियां किसी भी तरह से हुवावेई और जेडटीई के उत्पाद उपयोग नहीं कर सकेंगी।

स्वीडिश पोस्ट एंड टेलीकॉम अथॉरिटी' ने कहा कि जो दूरसंचार कंपनियां 5जी प्रौद्योगिकी के लिए अपने मौजूदा ढांचे का उपयोग करना चाहती हैं उन्हें भी सुनिश्चित करना होगा कि वह हुवावेई और जेडटीई के पहले से लगे उपकरणों को हटा लें। नियामक ने कहा कि ये शर्तें स्वीडन की सेना और सुरक्षा सेवाओं द्वारा की गयी समीक्षा के आधार पर तय की गयी हैं। हुवावेई ने इसे 'अचंभित करने वाला' और 'निराशाजनक' बताया।

हुवावेई को प्रतिबंधित करने वाले देशों में स्वीडन शामिल होने वाला सबसे नया देश है। उसके इस निर्णय से चीन की सरकार और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। अमेरिकी अधिकारियों ने हुवावेई को प्रतिबंधित करने के लिए यूरोप में बड़े पैमाने पर पैरवी की है।

स्वीडन के इस प्रतिबंध से घरेलू कंपनी एरिक्सन और फिनलैंड की नोकिया के सामने ज्यादा अवसर मौजूद होंगे। दोनों ही नेटवर्क उपकरण क्षेत्र में हुवावेई की प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं। स्वीडन की घरेलू सुरक्षा सेवा के प्रमुख क्लास फ्रिबर्ग ने चीन को स्वीडन के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि चीन खुद के आर्थिक विकास को बढ़ाने और सैन्य क्षमताएं विकसित करने के लिए साइबर जासूसी करा रहा है।

इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ को पहले दिन 39 प्रतिशत अभिदान मिला

मुंबई। एजेंसी

इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को बोली के पहले दिन 39 प्रतिशत अभिदान मिला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास उपलब्ध आंकड़े के अनुसार 517 करोड़ रुपये के आईपीओ के तहत कंपनी ने 11,58,50,001 शेयर बिक्री के लिये रखा है जबकि बोलियां 4,54,01,850 शेयर के लिये आयी। गैर-संस्थागत श्रेणी में निर्गम को 3 प्रतिशत और खुदरा निवेशकों के मामले में 85 प्रतिशत अभिदान मिला। आईपीओ के तहत 280 करोड़ रुपये का नया निर्गम लाया गया है और 7.20 करोड़ शेयर बिक्री के लिये पेशकश की गयी हैं। पेशकश के लिये कीमत दायरा 32 से 33 रुपये रखा गया है। इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 35 बड़े (एंकर) निवेशकों को 42,327,271 शेयर आबंटित कर 139.68 करोड़ रुपये जुटाये।

देशभर में एक दाम में सोना बेचेगी मालाबार गोल्ड

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

सोने एवं हीरा के आभूषणों के खुदरा स्टोरों का परिचालन करने वाली कंपनी मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने देश भर में सोने की एक समान कीमत की मुहिम की बुधवार को शुरुआत की। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसने 'वन इंडिया, वन गोल्ड रेट' की शुरुआत की है, जो देश के सभी राज्यों में एक समान सोने की दर पर 100 प्रतिशत बीआईएस हॉलमार्क सोने की पेशकश करता है। मालाबार ग्रुप के चेयरमैन अहमद एमपी ने कहा, "कोविड-19 महामारी से सभी क्षेत्रों में भारी उथल-पुथल मची हुई है, लेकिन सोने की मांग लगातार अधिक बनी हुई है। यह भारतीय उपभोक्ता की बचत और धन सृजन के उपाय के रूप में पीली धातु के प्रति आत्मीयता को दर्शाता है। 'वन इंडिया वन गोल्ड रेट' की हमारी पहल का उद्देश्य शुद्धता के साथ समझौता किये बिना उपभोक्ताओं को एक समान सोने की दर प्रदान करना है।"

नवनीत एजुकेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया नया ब्रांड HQ

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

एजुकेशन के क्षेत्र में एक विश्वसनीय ब्रांड नवनीत एजुकेशन लिमिटेड स्टूडेंट रेंज में स्टेशनरी प्रोडक्ट्सक की सफलता के बाद, नए ब्रांड एचक्यू (HQ) को लॉन्चम कर ऑफिस स्टेशनरी सेगमेंट में प्रवेश कर गया है। इस ब्रांड का लक्ष्य उन अधिकारियों को लक्षित करना है, जो अच्छी तरह से डिज़ाइन और तैयार किए गए उत्पोदों को पसंद करते हैं। इस रेंज में पेपर-बेस्ड स्टेशनरी प्रोडक्ट्से की पेशकश की गई है और इनकी डिजाइन ऐसी है जिन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्रोडक्ट्स समझने में बेहद आसान हैं। कंपनी ने प्रोडक्ट्स की कीमतों को आकर्षक रखा है और सामग्रियों को बाहर से मंगाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

एचक्यू के स्टेशनरी प्रोडक्टस को अपनी अभिनव और सरल डिजाइन, त्रुटिहीन गुणवत्ता और मजबूत उपयोगिता मूल्य के कारण कार्यस्थलों पर खूब लोकप्रियता मिल रही है। नए ब्रांड के साथ, नवनीत उन ग्राहकों की जरूरतें पूरी कर रहा है जोकि यंग अचीवर्स हैं और जिन्हें उन चीजों को लेकर काफी गहरी समझ है जो डिजाइन के लिहाज से अतुलनीय मूल्य प्रदान करते हैं। एचक्यू द्वारा पेपर-बेस्ड स्टेशनरी उत्पादों की एक व्या पक रेंज पेश की गई है। यह उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है, जो एकदम सही और स्टाइलिश एसेसरीज़ की तलाश में रहते हैं। एचक्यू ईज़ी डिस्क प्रमुख इनोवेशन में से एक है। इस नोटबुक में कोई भी पेजेज को शफल (फेरबदल) कर सकता है और उन्हेंत सेंट्रल डिस्क बाइंडिंग से आसानी से हटाकर जहां चाहें वापस लगा सकता है। इसी तरह, पीयू नोटबुक, लीगली 18, कैलीग्राफी गणेश आदि जैसे प्रोडक्ट्सर भी हैं, जिन्हें विभिन्न उपयोगकर्ताओं की जरूरतों और पसंद को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है। एचक्यू के लॉन्च के बारे में चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर श्री अभिजीत सान्याल ने कहा, हमने एचक्यू प्रोडक्ट्सर के लिए सामग्री का विकास और उसकी सोर्सिंग करते समय विशेष ध्यान रखा है। हम चाहते हैं कि हमारे उपभोक्ता न केवल किताबों के स्टाइलिश डिजाइन, बल्कि संपूर्ण लेखन अनुभव से भी खुश हों। विशेष रूप से ऑफिस स्पेस के लिए उत्पादों की पेशकश करने वाले बहुत ब्रांड नहीं हैं और पूरी श्रेणी अनब्रांडेड और कमोडिटाइज्ड उत्पादों विशेष रूप से पेपर श्रेणी से भरी पड़ी है। नवनीत ने पेपर स्टेशनरी निर्माण की विशेषज्ञता का उपयोग करके इस अंतर को भरने का फैसला किया है और ऐसे उत्पाद तैयार किए हैं जिनकी हर कोई प्रशंसा करेगा।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।